पुनरीक्षण सिविल

माननीय मेहर सिंह, मुख्य न्यायाधीश के समक्ष

इंद्रजीत सिंह, -याचिकाकर्ता।

बनाम

राज कुमार गुप्ता और अन्य, -प्रतिवादी

सिविल संशोधन संख्या 219 /1966

1 मार्च 1968

पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 (1953 का चतुर्थ)—एस. 79—दंड प्रक्रिया संहिता (1898 का अधिनियम V)—एस.एस. 480 और 481—दंड संहिता (1860 का एक्सएलवी)—एस. 228—पंचायत के समक्ष न्यायिक कार्यवाही–एस.एस. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 480 और 481 - चाहे लागू हो - धारा 481 की आवश्यकताएं - बताया गया - अपराधी अदालत के समक्ष बयान देने के बजाय पीठासीन अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करता है और कीचड़ फेंकता है - बयान देने का अवसर - चाहे दिया गया समझा जाए।

माना गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धाराएं 480 और 481 पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम के तहत पंचायत के समक्ष न्यायिक कार्यवाही पर लागू होती हैं, लेकिन इस अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) के प्रावधान के अनुसार जुर्माने की अधिकतम राशि सीमित है रु. 25. जहां दंड संहिता की धारा 228 के तहत कोई अपराध ग्राम पंचायत की दृष्टि या उपस्थिति में किया जाता है, तो अपराधी को हिरासत में लिया जा सकता है और फिर धारा 480 और निम्नलिखित धारा 481 के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता.

माना गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 481 की उप-धारा (1) की आवश्यकताएं हैं (ए) कि अपराध का गठन करने वाले तथ्यों को न्यायालय द्वारा बताया जाना चाहिए, (बी) कि बयान (यदि कोई हो) द्वारा दिया गया है अपराधी को दर्ज करना होगा, और (सी) निष्कर्ष और सजा बतानी होगी। इसे रिकॉर्ड करने का आदेश न्यायालय को दिया गया है और जाहिर तौर पर यह अनिवार्य है। इसके अलावा, यदि अपराध दंड संहिता की धारा 228 के तहत है, तो

इस धारा की उप-धारा (2) के अनुसार, रिकॉर्ड को आगे (डी) न्यायिक कार्यवाही की प्रकृति और चरण को दिखाना होगा जिसमें न्यायालय ऐसा करता है व्यवधान या अपमान बैठा था, और (ङ) व्यवधान या अपमान की प्रकृति। इसलिए, दंड संहिता की धारा 228 के तहत एक मामले में, जहां अदालत की अवमानना न्यायालय की दृष्टि या उपस्थिति में की जाती है, रिकॉर्ड को उन पांच शर्तों का पालन करना चाहिए।

माना गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 481 की उपधारा (1) अपराधी के बयान की रिकॉर्डिंग को ध्यान में रखती है, यदि वह कोई बयान देता है, जो स्पष्ट रूप से तभी हो सकता है जब उसके पास ऐसा बयान देने का अवसर हो। हालाँकि, यदि अवसर है, लेकिन न्यायालय के समक्ष कोई बयान देने के बजाय अपराधी पीठासीन अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करता है और कीचड़ फेंकता है, तो उसकी ओर से यह तर्क स्वीकार्य नहीं है कि उसे जवाब में बयान देने का कोई अवसर नहीं मिला। उन पर जो आरोप लगाया गया या उनका बयान नहीं लिया गया.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिका, जिसमें प्रार्थना की गई है कि माननीय उच्च न्यायालय अपनी अधीक्षण शक्ति का प्रयोग कर सकता है और प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पारित 27 अगस्त, 1965 के आदेश को रद्द कर सकता है।

याचिकाकर्ता के वकील जी आर पाल सिंह।

प्रतिवादियों की ओर से वकील आर. पी. बाली।

निर्णय.

माननीय मुख्य न्यायाधीश मेहर सिंह-3 फरवरी, 1965 को गांव जमीतगढ़ की पंचायत हुई, जिसमें इंद्रजीत सिंह, सरपंच, अध्यक्षता और कोरम पूरा था, पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 की धारा 21 के तहत सरवन सिंह, प्रतिवादी 2 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। (1953 का पंजाब अधिनियम 4), एक रास्ते पर अतिक्रमण के लिए, और जब उन्होंने मामले में अपने फैसले की घोषणा की, तो प्रतिवादी 2' ने उन्हें गाली देना शुरू कर दिया और चुनौती दी कि वह देखेंगे कि कैसे और कौन उनसे जमीन खाली कराएगा। . पंचायत ने उसे मामला समझाने और यह समझाने की कोशिश की कि स्थिति क्या है, लेकिन उसने तब भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इस तरह प्रतिवादी 2 ने पंचायत की कार्यवाही में बाधा डाली और सदस्यों पर कीचड़ उछाला और उनका अपमान किया।

दंड संहिता की धारा 228 प्रदान करती है-

"जो कोई भी जानबूझकर किसी लोक सेवक का अपमान करता है, या किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न करता है, जबकि ऐसा लोक सेवक न्यायिक कार्यवाही के किसी भी चरण में बैठा है, तो उसे एक अवधि के लिए साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है।" एक हजार रुपये तक बढ़ाएँ, या दोनों के साथ"। 1953 के पंजाब अधिनियम 4 की धारा 79 में लिखा है-

"79. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 480 से 482 के प्रावधान इस अधिनियम के तहत न्यायिक कार्यवाही पर लागू होंगे:

बशर्ते कि न्यायालय की अवमानना के लिए लगाया गया जुर्माना पच्चीस रुपये से अधिक नहीं होगा।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 512.517 एवं 522 के प्रावधान। 1898. पंचायत के समक्ष आपराधिक कार्यवाही पर लागू होगा, और यदि दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 517 और 522 के संबंध में पंचायत द्वारा दिए गए किसी भी आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो पंचायत उसे निकटतम मजिस्ट्रेट को भेज देगी। जो इसे निष्पादित करने के लिए आगे बढ़ेगा जैसे कि यह स्वयं द्वारा पारित आदेश था।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 480 और 481 हैं-

"480. (1) जब भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180, या धारा 228 में वर्णित कोई भी ऐसा अपराध किसी सिविल, आपराधिक या राजस्व न्यायालय की दृष्टि या उपस्थिति में किया जाता है, न्यायालय अपराधी को हिरासत में ले सकता है; और उसी दिन न्यायालय उठने से पहले किसी भी समय, यदि वह उचित समझे, अपराध का संज्ञान ले सकता है और अपराधी को दो सौ रुपये से अधिक का जुर्माना नहीं लगा सकता है, और, भुगतान न करने पर, एक अवधि के लिए साधारण कारावास, जिसे एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है, जब तक कि ऐसा जुर्माना पहले न चुकाया जाए।

(1) ऐसे प्रत्येक मामले में न्यायालय अपराध का गठन करने वाले तथ्यों, अपराधी द्वारा दिए गए बयान (यदि कोई हो) के साथ-साथ निष्कर्ष और सजा को दर्ज करेगा।

(2) यदि अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 228 के तहत है, तो रिकॉर्ड न्यायिक कार्यवाही की प्रकृति और चरण को दिखाएगा जिसमें न्यायालय ने बाधा डाली या अपमान किया, और रुकावट या अपमान की प्रकृति दिखाई जाएगी।

इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धाराएं 480 और 481 1953 के पंजाब अधिनियम 4 के तहत पंचायत के समक्ष न्यायिक कार्यवाही पर लागू होती हैं, लेकिन इस अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) के प्रावधान के अनुसार जुर्माने की अधिकतम राशि सीमित है। से रु. 25. जहां दंड संहिता की धारा 228 के तहत कोई अपराध अदालत की नजर में या उसकी उपस्थिति में किया जाता है, तो इससे अपराधी को हिरासत में लिया जा सकता है और फिर उसके खिलाफ धारा 480 और निम्नलिखित धारा 481 के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता.

संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिकाकर्ता-सरपंच की याचिका का प्रस्ताव, अनुलग्नक ए, ऊपर बताए गए तथ्यों को विस्तार से देता है। पंचायत द्वारा प्रतिवादी 2 के विरुद्ध मामला तय करने के बाद, उसने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। जब पंचायत ने उसे मामले को समझाने की कोशिश की, तो उसने उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोका बल्कि उनके साथ और दुर्व्यवहार किया। इतना ही नहीं उन्होंने पंचायत सदस्यों पर भी कीचड़ उछाला. इसलिए पंचायत ने प्रतिवादी 2 को दंड संहिता की धारा 228 के तहत अदालत की अवमानना के अपराध के लिए दोषी ठहराया, 1953 के पंजाब अधिनियम 4 की धारा 79 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 480 और 481 के तहत कार्यवाही की, और उसे जुर्माने की सजा सुनाई। रु. 25. इसके विरूद्ध प्रतिवादी 2 ने पंजाब अधिनियम 4 सन् 1953 की धारा 51 के तहत जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन दिया, जिसकी सुनवाई एवं निस्तारण श्री राज कुमार गुप्ता द्वारा किया गया। प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतिवादी 1, 27 अगस्त, 1965 को। विद्वान मजिस्ट्रेट ने प्रतिवादी 2 की दोषसिद्धि और सजा को इस आधार पर रद्द कर दिया कि 'याचिकाकर्ता (प्रतिवादी 2) को जुर्माने से पहले कारण बताने के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। ' लगाया गया था.

यह विद्वान मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध है कि याचिकाकर्ता-सरपंच ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत यह याचिका दायर की है। याचिका में दिए गए आधार यह हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 480 और 481 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय की दृष्टि या उपस्थिति में किए गए अवमानना के अपराध के मामले में, कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिए। प्रतिवादी 2 न तो पूर्ण था और न ही अनिवार्य, कि जो कुछ हुआ उस पर पंचायत अपनी राय पर भरोसा कर सकती है और अपराधी को दंडित करने के लिए आगे बढ़ सकती है, और पंचायत ने प्रतिवादी

2 को अपने आचरण से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की और गंदी गालियां देना और बाधा डालना जारी रखा। उनकी कार्यवाही. प्रतिवादी 2 द्वारा याचिका पर एक रिटर्न दायर किया गया है जिसमें उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि पंचायत का कोई उचित कोरम था या वे उस दिन न्यायिक कार्यवाही कर रहे थे जब वह उनके सामने पेश हुए थे। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि उन्होंने पंचायत के साथ दुर्व्यवहार किया या सदस्यों पर कीचड़ फेंका. उन्होंने कहा है कि याचिकाकर्ता-सरपंच से दुश्मनी के कारण पंचायत द्वारा उनके खिलाफ यह मामला बनाया गया था।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 481 की उप-धारा (1) की आवश्यकताएं हैं (ए) कि अपराध का गठन करने वाले तथ्यों को न्यायालय द्वारा बताया जाना चाहिए, (बी) कि अपराधी द्वारा दिया गया बयान (यदि कोई हो) दर्ज किया जाना चाहिए, और (सी) कि निष्कर्ष और सजा बताई जानी चाहिए। इसे रिकॉर्ड करने का आदेश न्यायालय को दिया गया है और जाहिर तौर पर यह अनिवार्य है। इसके अलावा, यदि अपराध दंड संहिता की धारा 228 के तहत है, तो इस धारा की उप-धारा (2) के अनुसार, रिकॉर्ड को आगे (डी) न्यायिक कार्यवाही की प्रकृति और चरण को दिखाना होगा जिसमें न्यायालय ऐसा करता है व्यवधान या अपमान बैठा था, और (ङ) व्यवधान या अपमान की प्रकृति। इसलिए, दंड संहिता की धारा 228 के तहत एक मामले में, जहां अदालत की अवमानना न्यायालय की दृष्टि या उपस्थिति में की जाती है, रिकॉर्ड को उन पांच शर्तों का पालन करना चाहिए। इस मामले में दंड संहिता की धारा 228 के तहत अपराध का गठन करने वाले तथ्य पंचायत के प्रस्ताव में बताए गए हैं। इसके निष्कर्ष और उस पर प्रतिवादी 2 को दी गई सजा भी दर्ज की गई है। वह चरण भी दर्ज किया गया है जिस पर प्रतिवादी 2 ने न्यायिक कार्यवाही में बाधा डाली और पंचायत के साथ दुर्व्यवहार और अपमान किया। प्रस्ताव में व्यवधान और अपमान की प्रकृति भी स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है। विचार के लिए केवल एक घटक शेष है और वह है दूसरा, क्या प्रतिवादी 2 द्वारा दिया गया बयान (यदि कोई हो) लिया गया था या नहीं लिया गया था? 1953 के पंजाब अधिनियम 4 की धारा 51 के तहत पंचायत की कार्यवाही पर विचार करते समय विद्वान मजिस्ट्रेट की राय थी कि प्रतिवादी 2 के खिलाफ कथित अपराध के लिए पंचायत द्वारा कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया था और इसी कारण अकेले प्रतिवादी 2 की दोषसिद्धि हुई। और सजा बरकरार नहीं रखी जा सकी. याचिकाकर्ता-सरपंच के विद्वान वकील का तर्क है कि इसमें विद्वान मजिस्ट्रेट ने मामले के तथ्यों के प्रति गलत दृष्टिकोण अपनाया है, क्योंकि पंचायत के प्रस्ताव में ही कहा गया है कि जब प्रतिवादी

2 ने उन्हें गाली देना शुरू कर दिया और चुनौती देना शुरू कर दिया। सदस्यों ने अपने आदेश के अनुपालन की मांग करते हुए उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि क्या परिस्थितियाँ हैं और क्या किया जा रहा है, लेकिन प्रतिवादी 2 ने उनकी बात सुनने के बजाय, उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन पर कीचड़ उछाला। विद्वान वकील बताते हैं कि जबकि पंचायत ने प्रतिवादी 2 को उसके आचरण के सार और प्रकृति और उसके प्रभाव को समझाने के लिए हर संभव प्रयास किया, दूसरे शब्दों में, वह जो अपराध कर रहा था उसकी प्रकृति, उसने पंचायत के सदस्यों को इसकी अनुमति नहीं दी। ऐसा करने के बजाय, वह उनके साथ दुर्व्यवहार करने और उन पर कीचड़ उछालने के अपने आचरण पर कायम रहा। विद्वान वकील का कहना है कि इन परिस्थितियों में, यह कहना कि प्रतिवादी 2 को उस अपराध के तथ्यों पर अपना जवाब देने का अवसर नहीं दिया गया है जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया है, सही नहीं है। प्रतिवादी 2 के पक्ष में सबसे पहले विद्वान वकील ने बताया कि उनके हलफनामे से पता चलता है कि पंचायत उस विशेष दिन पर कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं कर रही थी और इसके अलावा प्रतिवादी 2 ने कभी भी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। वह वास्तव में याचिकाकर्ता-सरपंच के साथ अपनी दुश्मनी के कारण मामले में शामिल था। यह गुण-दोष के आधार पर मामला है और संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत इस तरह की याचिका में इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। यहां विचार करने योग्य एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या विद्वान मजिस्ट्रेट का आदेश वैध है या क्या उसने पंचायत के आदेश को रद्द करने और प्रतिवादी 2 पर लगाए गए जुर्माने को माफ करने में अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है? इस संबंध में पहला मामला जिस पर प्रतिवादी 2 के विद्वान वकील भरोसा करते हैं, वह देवेन्द्र नाथ मैत्रा बनाम सम्राट (1) है जिसमें उस समय एक मजिस्ट्रेट के कारण हुई रुकावट के कारण दंड संहिता की धारा 228 के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया था। वह न्यायिक कार्य कर रहा था, लेकिन वहां वह अदालत नहीं थी जिसके समक्ष अपराध किया गया था, जिसने अवमाननाकर्ता के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 480 और 481 के तहत कार्यवाही की थी। एक अन्य न्यायालय में शिकायत की गई थी और यह वह अन्य न्यायालय था जिसने दंड संहिता की धारा 228 के तहत अपराध के लिए अवमाननाकर्ता पर मुकदमा चलाया था, जो एक सम्मन मामला था, और यह उन परिस्थितियों में था कि विद्वान न्यायाधीश ने धारा 242 की ओर इशारा किया था दंड प्रक्रिया संहिता की मांग है कि अभियुक्त को यह बताया जाना चाहिए कि उसका अपराध वास्तव में क्या है। उस स्थिति में उस धारा के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था। जाहिर है उस मामले का मौजूदा मामले के तथ्यों पर कोई असर नहीं है। दूसरा मामला जिसका प्रतिवादी 2 के विद्वान वकील ने संदर्भ दिया है वह

कृष्ण चंद्र भोमिक बनाम सम्राट (2) है। यह दंड संहिता की धारा 228 के तहत एक अपराध का मामला था जो मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में किया गया था, जिसने अवमाननाकर्ता को रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। 50 अपील में तर्क यह था कि मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना था क्योंकि अवमाननाकर्ता को बयान देने के लिए नहीं बुलाया गया था और आपराधिक संहिता की धारा 481 के अनुसार कोई बयान दर्ज नहीं किया गया था। प्रक्रिया। अपील की सुनवाई कर रहे विद्वान सत्र न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि यह सिद्धांत कि किसी व्यक्ति की निंदा करने से पहले उसे सुना जाना चाहिए, ऐसे मामलों में लागू नहीं होता है जहां एक्सप्रेस कानून द्वारा विशेष प्रक्रिया प्रदान की गई है। विद्वान न्यायाधीश, पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, सत्र न्यायाधीश की उस राय से सहमत नहीं थे, और, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 481 की उप-धारा (1) में आने वाले शब्दों 'यदि कोई हो' के संदर्भ में, वे देखा गया- "अभिव्यक्ति 'यदि कोई हो' से यह संकेत मिलता है कि न्यायालय आरोपी को बयान देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि उसे उसे बयान देने का अवसर नहीं देना चाहिए"। यह मामला प्रतिवादी 2 की मदद नहीं करता है क्योंकि वर्तमान मामले के तथ्यों में भी जब पंचायत के सदस्यों ने प्रतिवादी 2 क्या कर रहा था उसकी स्थिति और परिस्थितियों को समझाने की कोशिश की, तो उसने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी, बल्कि उन्होंने उनके साथ और दुर्व्यवहार किया। और उन पर कीचड़ उछाला. ताकि कृष्ण चंद्र भोमिक का मामला वर्तमान मामले से अलग हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 481 की उपधारा (1) अपराधी के बयान की रिकॉर्डिंग को ध्यान में रखती है, यदि वह कोई बयान देता है, जो स्पष्ट रूप से केवल तभी हो सकता है जब उसके पास ऐसा बयान देने का अवसर हो। हालाँकि, जैसा कि वर्तमान मामले में है, यदि अवसर है, लेकिन कोई भी बयान देने के बजाय अपराधी आगे गालियाँ देता है और कीचड़ फेंकता है, जैसा कि प्रतिवादी 2 ने कहा है कि जहाँ तक पंचायत का संबंध है, एक तर्क स्वीकार्य नहीं है उनकी तरफ से कहा गया कि उन्हें अपने ऊपर लगे आरोप के जवाब में बयान देने का कोई मौका नहीं मिला या उनका बयान नहीं लिया गया. इस दृष्टिकोण में विद्वान मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और यह पाया जाएगा कि यह उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किया गया है।

इसलिए याचिकाकर्ता-सरपंच की यह याचिका स्वीकार की जाती है, और मजिस्ट्रेट के 27 अगस्त, 1965 के आदेश को इस निर्देश के साथ रद्द कर दिया जाता है कि वह अब पंजाब अधिनियम 4 की धारा 51 के तहत प्रतिवादी 2 के

आवेदन का निपटान करने के लिए आगे बढ़ेंगे। 1953 की योग्यता के आधार पर और कानून के अनुसार। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आयुष गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पलवल, हरियाणा